MR. CHAIRMAN: Is this time scheduly being followed that is why they want to know.

SHRI J. VENGAL RAO: Sir, there is slight delay. I answered that it will be completed by the end of the Seventh Plan.

MR. CHAIRMAN: That he has already said. Now, question No. 363

SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Sir, I want to ask only one question whether there are any diesel engine proposals? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am asking about question No 363.

SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Sir, I raised my hand on the earlier question. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You do not want to ask Question No. 363.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, some chance must be given to backbenchers.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 363.

Use of Compressed Gas as Automotive Fuel

*363. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:†
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether ONGC has conducted trials for the use of compressed natural gas as an automative fuel and also for generation of electricity;

(b) if so, what are the findings in terms of economy in transportation costs and saying of valuable foreign exchange by way of cutting the imports and also its impact on environment; and

(c) what are the details of the Government's plan for commercial use thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) to (c) ONGC have conducted trials for use of compressed natural gas (CNG) as an automotive fuel to replace diesel/petrol. One petrol generator set has been convrted to CNG on an experimental basis. The saving likely to arise with the substitution of CNG can be estimated only after detailed experimentation is completed. From the environmental point of view, CNG is a good fuel. The possibility of commercial use of CNG can be looked at after analysing results of the experiments.

श्री शंकर सिंह वाघेला : चेयरमैन साहब, गैस के प्रयोग के संबंध में मैंने दो प्रश्न पूछे थे, लेकिन मेरे प्रश्न के एक ही भाग का जवाब दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गैस को आज कितना फ्लेयर अप किया जा सकता है, इसका हिसाब ओ० एन० जी० सी० और मंत्रालय के पास नहीं है। गैस बेकार में जलती रहती है तो हमारा दिल जलता है। इतना धन देश का बेकार जा रहा है। गैस के प्रयोग के बारे में, इसके टोटल प्रयोग के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन वह चिन्ता नहीं की जाती जाती... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप सवाल कीजिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला : आप जानते हैं कि पैट्रोल बहुत महंगी चीज है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 15 साल पहले एल० पी० जी० से कार चलाई गई थी। ऐसा प्रयोग कानपुर में एक सरदार जी ने किया था, उसने इसको देखा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया और ओ० एन० जी० सी० का गैस का प्रयोग कार चलाने के लिए होता है, यह बात कब मालूम पड़ी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shanker Sinh Vaghela.

हूं कि आपने इस संबंध में कब से परीक्षण किया है और कब तक इस परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण करके व्हीकल्स के लिए आप गैस के प्रयोग को एलाउ करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय वर, मैं आदरणीय सदस्य से सहमत हूं कि इस पर विचार करना चाहिए । हम सब लोगों को याद होगा कि, जब पिछला युद्ध चल रहा था तो पैट्रोल की बहुत कमी हो गई थी । उस वक्त सी० एन० जी० तो नहीं, लेकिन कोल गैस प्लान्ट लगाये गये थे बुसेल्ज में । हम लोगों की भी यह कोशिश है कि कार में इसका प्रयोग कैसे करें । हमारी एक पायलट प्रोजेक्ट है कि डीजल इंजिन में, कार में, इसको कैसे करें । यह भी देखना है कि मैथनोल बनाकर हम गैस प्रयोग कर सकें । यह सब पायलट प्रोजेक्ट की अवस्था में हैं । सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमें पहला कार्य यह करना पड़ेगा कि हमें इंजिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा । उसके लिए किट्स मंगा करके कुछ बसों को, कुछ कारों को कंवर्ट भी किया है। पहला काम तो कंवर्जन का है । दूसरे नम्बर पर फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। सी० एन० जी० के लिए नैटवर्क पैदा करना पड़ेगा । ये सब चीजें अभी एक्सपैरिमेंटल स्टेज में हैं । गवर्नमेंट को इस बात की चिन्ता है कि हमारे पास जो गैस उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जाय । गैस का उपयोग फर्टिलाइजर्स प्लान्ट के लिए पावर प्लांट्स के लिए और पैट्रोकैमिकल्स प्लान्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा हो, यह हमारी कोशिश है । लिक्विड पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स के लिए भी प्राकृतिक गैस का उपयोग हो, इसके लिए भी काम चल रहा है । इसके लिए हमारी तीन-चार पायलेट प्रोजेक्ट्स चल रही हैं । ये सब एक्सपैरिमैन्टल स्टेज में है और पिछले 1–2 साल से चल रहे हैं । हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे इस की आवश्यकता होगी, इसको एडोप्ट किया जा सकता है ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : आप इसको कब तक कर लेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : इसके लिए कोई निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन दो-तीन साल में हो जाना चाहिए । इसका आर्थिक पहलू भी है । भारतवर्ष में अभी हम इस स्टेज में नहीं आए हैं कि प्राकृतिक गैस हम मोटर के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें । हमारी पहली प्राथमिकता फर्टिलाइजर के लिए, पावर के लिए और डोमेस्टिक प्रयोग के लिए है । उसके बाद मोटर की बात आती है । हमारी रिफाइनरीज में पैट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । असल में हमें उसके कंजम्पशन को कंटेन करना है । पैट्रोल के लिए दिक्कत नहीं है । गैस के अन्य प्रयोगों में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां भी हैं ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय मंत्री जी ने फर्टिलाइजर के लिए गैस के प्रयोग की बात कही । आप इस बात को छोड दीजिए । फर्टिलाइजर के इम्पोर्ट-और एक्सपोर्ट के संबंध में ढेरों प्रयोग किए गए हैं, आप इसको छोड़ दीजिए । गैस के इलैक्ट्रिसिटी में प्रयोग के संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि कितने राज्यों ने जहां पर गैस निकलती है, गैस के कंवर्जन के लिए आपके पास प्रोपोजल भेजे हैं और कितने राज्यों को उन प्रोपोजल का आप ने जवाब दिया है, और कब तक आप इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : श्रीमन, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ? व्यक्तिगत रूप से विद्युत की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों के लिए, कृषि के लिए और घरेलू उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता को हम समझते हैं । हम आसाम इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे गैस सप्लाई कर रहे हैं। त्रिपुरा का 0.13 कर रहे हैं, महाराष्ट्र को 3 मिलियन कर रहे हैं, टाटा इलेक्ट्रिसिटी का मिलाकर, गुजरात का 0.35 कर रहे हैं दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने कमिटमेंट के बारे में पूछा है तो जो वायदे हमने किये हैं हमने तीन पावर प्लान्ट एन० टी० पी० सी० के एक

तो फाल बैक बैसिस पर और दो फर्म बैसिस पर किये है और चार मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का वायदा किया है । एक आंता में है, एक क्वास में है और एक ओरिया में है । कथवगुरी में एक मिलियन क्यूबिक मीटर का किया है । आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 0.4 किया है । आंध्र प्रदेश में दिक्कत यह पड़ रही है कि जोदावटी डेल्टा का जो आईलैंड है उसको क्रास करना था । हमने यह निश्चय किया है कि 5–6 महीने में इसको अंडर ग्राउंड करके क्रास कर ले ताकि नरसापुर की गैस उनको दे सकें । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमने कमिटमेंट किया है । तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 0.4 किया है, त्रिपुरा को भी किया है । हर जगह कोशिश हो रही है । इसको दो भाग हैं जो मैं संक्षेप में बता दूं । एक तो वह भाग जहां कि यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां बड़े गैस प्लान्ट हों और जो आइसोलेटेड रिमोट जगहों में राजस्थान और गुजरात में मिल रही है यदि वहां एक मेगावाट या आधा मेगावाट का पावर प्लान्ट लगाया जाय तो हम उसका स्वागत करते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, एक ओर मंत्री जी गैस विद्युत परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और दूसरी ओर जब इसका पेट्रोल या डीजल के स्थान पर उसका उपयोग हो तो वहां वे कहते हैं कि हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि उसका फर्टिलाइजर और कैमिकल यूज करें । मैं जानकारी के लिये यह बता दूं कि फर्टिल इजर और कैमिकल हमें जितनी आपके पास गैस है उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं । 24 प्रतिशत हिन्दुस्तान की गैस को हम हर रोज जला देते हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्राकृतिक गैस का हमारे पास इतना भंडार है कि हम उसमें स्वयं पूर्ण हो सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं और 10 हजार रुपया एक ट्रक में खर्च करके पर किलोमीटर 50 पैसे बचा सकते है । इसलिये इसको देखते हुए क्या सरकार निजी रूप में आटोमेटिक फ्यूल के नाते गैस को इसमें उपयोग करने की अनुमति देगी ? यह गैस सब जगह उपलब्ध है । यह बम्बई में भी है, त्रिपुरा में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है । इसलिये इसको देखते हुए इसके लिये किसी नेशनल ग्रिड बनाने की योजना जो सालों से सरकार के पास पड़ी है, उस पर विचार करेंगे ताकि इसके लिये एक राष्ट्रीय ग्रिड बन सके ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रिड का सवाल आ रहा है । लेकिन राष्ट्रीय ग्रिड तो इस तरह से बनता है पहले क्षेत्रीय ग्रिड बनेंगे जैसे कि पावर का बना है और वह इस तरह से बन ये जाये कि आखिर में वह राष्ट्रीय ग्रिड में आ जायं । अभी यह बहुत थोड़ी मात्रा में कई जगह यह उपलब्ध है । बड़ा मात्रा में हमारे पास बम्बई हाई में है, बेसिन में है, त्रिपुरा में है । अब त्रिपुरा की कठिनाई आप जानते हैं, अन्तरराष्ट्रीय कठिनाई है क्योंकि बंगला देश बीच में पड़ता है । तो बजाय इसके कि नेशनल ग्रिड का काम हम शुरू करें पहले हमें रीजनल ग्रिड में लेकर इसको शुरू करना चाहिए फिर आगे इसका समन्वय करेंगे, इसको इन्टीग्रेटेड करेंगे । मैं इस बात से सहमत हूं और इसके लिये एक बड़ा संघटनात्मक ढांचा खड़ा करना पड़ेगा ताकि उसका उपयोग हम कर सकें ।

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप निजी प्रयोग की अनुमति देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, विशेष कारण से अगर आपको पेट्रोल में कमी लगती है और आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेरीमेंट की तौर पर करें तो इसकी अनुमति मैं आपको दे दूंगा । लेकिन इसके ऐसा न हो कि सब लोग इसकी अनुमति मागने लगें ।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether experiments have been made for use of natural gas or LPG for flying machines, such as helicopters and others and also whether any experimentation is being carried out by his Ministry or others, that is in his knowledge, on use of hydrogen gas for automative purpose.

SHRI BRAHM DUTT: I have already submitted that we are experimenting with using CNG and LPG for trucks and motor vehicles. As far as my information goes, helicopters and aircraft are out of question at present.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Are you considering any work being done on hydrogen gas for automative purpose ?

SHRI BRAHM DUTT: I am concerned with natural gas. Some other department will be dealing with hydrogen gas.

SHRI PRAVATHANENI UPENDRA: Sir, the Minister has mentioned about the commitment of the ONGC for supply of gas to the State Electricity Boards and he also mentioned about Andhra Pradesh Electricity Board. Several firms from abroad are offering full financial assistance for assistance for installing gas turbines for converting gas into electricity. The Minister of Energy is also here. But all these proposals are kept pending with the Finance Ministry here. They are not being cleared, though there is a power crisis in the country and gas is going waste in the Krishna-Godavari basin. These proposals have been pending for months together with the Finance Ministry. Will both of them together influence the Finance Ministry to clear these proposals?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, first of all, it is not correct to say that gas is being wasted in Krishna-Godavari basin. I have been there two months back. The production centres have been located. They have to be linked The greatest hurdle is the Vashishta river. The Finance Ministry has been generous enough to allow us to go ahead with the project so that we can cross the Vashishta river within 6 months and supply it to the power house which is going to be set up near Narasapur.

As far as private generation is concerned, it is our policy to allow generation to a certain extent under certain restrictions. This matter can be taken up by the Andhra Pradesh Government with the Energy Ministry.

SHRI PRAVATHANENI UPENDRA: Sir, this is not private. The proposal is for State Electricity Board.

SHRI BRAHM DUTT: The Finance Ministry is to consider that on merit, whether it will be easier, whether it will be very economical to import it, or BHEL can manufacture it.

SHRI PRAVATHANENI UPENDRA: BHEL are not able to supply.

SHRI BRAHM DUTT: I can assure you about the availability of gas as and when possible.

SHRI PRAVATHANENI UPENDRA: That I know. Mr. Vengal Rao is there and he can tell us.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): There is no proposal from the State Electricity Board.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA Sir, he is very wrong. The Minister has confirmed that it is there with the Economic Affairs Ministry. How can he say that there is no proposal? He always gives on-the-cuff answers.

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Sir, the Minister has referred to methanol as one of the substitutes for automative fuel which we get as a bye-product of molasses, which is agan an agricultural produce coming out of sugarcane. Some global economists are making experiments with methanool. I would like to know whether we are also making experiments in any part of the country in this direction.

SHRI BRAHM DUTT: We are trying to produce methanol from natural gas.

MR. CHAIRMAN: That is what he is concerned with. Question No. 364.

Study report of the Institute of Cost and Works Accountants on working capital Management of Public sector undertakings

*364. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:†
SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have examined the study report of the Institute of Cost and Works Accountants of India on the Working Capital Management in respect of Public Sector Undertakings, revealing that there was enough scope for reduction of working capital of PSUs; and

(b) if so, what are the findings and recommendations contained in the report and what is Government's response to each one of them?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Institute of Cost and Works Accountants of India Undertook a study on the Working Capital Management in a few selected Public Sector Undertakings at the instance of Government and submitted its report in August, 1987. The report has pointed out the common areas of blockade of funds in Public Sector and has pointed out posibility of reduction of working capital of the Public Sector Undertakings covered by the study.

The recommendations contained in the report are annexed. (*See* below).

The report is under consideration of the Government in consultation with the concerned Public Sector Undertakings.

Recommendations and Guidelines

2.1 Enterprises with extreme working capital situations like Neyveli Lignite Corporation (with high working capital to Turnover Ratio) and Enterprises with negative Working Capital Turnover Ratio like Hindustan Fertilizers Corporation and Delhi Transport Corporation should reorient their working capital strategies to bring a balance in working capital structure of the Company. The holding of Sundry Creditors should be srtongly discouraged.

2.2 The companies should adopt Budgetary Control System for Working Capital Control. Over the period proper steps should be taken for Scientific Assessment of Working Capital requirement with specific Targets of reduction of the levels every year.

2.3 There should be a Senior Executive in Finance (Financial Controller and above) primarily responsible for controlling Working Capital at the Corporate Level and Deputy General Manager & above responsible at unit level.

2.4 Specific guidelines identifying the limits and target (both in terms of "Days" consumption|sales and Monetary impact) for every company unitwise must be specified and followed up by the coordinating executive. Unless specific responsibility is assigned to the individuals, the task of Working Capital Control cannot be carried out.

2.5 Every company is to form a small team of 2/3 members under

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Atal Bihari Vajpayee.